बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्षः 24 ● अंकः 221 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 19 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्यः 3 रूपया ● पृष्ठः 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

बड़ा फैसला- ग्रुप सी पदों पर पूर्व-अग्निवीरों के लिए मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण; उपराज्यपाल संधू का निर्देश

नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। उन्होंने पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे ग्रुप ह पदों पर आरक्षण की घोषणा की। यह आरक्षण पूर्व-अग्निवीरों के लिए 20 फीसदी होगा। संधू ने मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने दिल्ली के सरकारी विभागों में पूर्व-अग्निवीरों को आरक्षण देने की रणनीति की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया मंच x पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप लागू की जा रही है।

टेलीग्राम बैन पर हाईकोर्ट में सुनवाई - कोर्ट में हुई तीखी बहस, आदेश में कानूनी खामियों का दावा

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। टेलीग्राम ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति तेजस कारिया की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। टेलीग्राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अंतिम आदेश पर दलीलें देने को कहा। ध्रुव मेहता ने आदेश में कानूनी खामी बताई। उन्होंने कहा कि यह केवल अंतरिम निर्देश की पुष्टि करता है। हाईकोर्ट ने इसे एक स्वतंत्र आवश्यकता बताया। कोर्ट ने कहा कि आदेश की पुष्टि या उसे पलटना हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। ध्रुव मेहता ने एक प्रावधान का जिक्र किया। इसके अनुसार सचिव का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। उन्हें लिखित में कारण बताते हुए निर्देश जारी करने का अधिकार है। उपलब्ध जानकारी पर सोच-विचार आदेश में होना चाहिए। कोर्ट ने ध्रुव मेहता के तर्कों को दोहराया। उन्होंने प्रतिबंध के अधिकार के स्वरुप पर सवाल उठाया। ध्रुव मेहता का कहना था कि यह आपातकालीन स्थिति नहीं है। उनका तर्क था कि केवल जानकारी को ब्लॉक किया जा सकता है, पूरे एप को नहीं। उन्होंने सचिव द्वारा सोच-समझकर निर्णय लेने और आनुपातिकता के सिद्धांत पर भी जोर दिया। ध्रुव मेहता ने 16 जून के विवादित संचार का जिक्र किया। कोर्ट ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के प्रयासों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि टेलीग्राम को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत सावधानी बरतनी होगी। टेलीग्राम एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। धारा 79 एक स्वतंत्र दायित्व है, जिसका धारा 69ए से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने धारा 69ए के तहत मिली शक्तियों के सही इस्तेमाल पर ध्यान देने को कहा। ध्रुव मेहता ने बताया कि एनटीए की ओर से एक आपातकालीन अनुरोध आया था। कोर्ट ने कहा कि यह आपातकालीन था या नहीं, इसका फैसला प्राधिकरण करेगा।ध्रुव मेहता ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एनटीए का अनुरोध पढ़कर सुनाया। पीठ ने बताया कि आपातकालीन स्थिति के लिए तीन चरण होते हैं। इनमें नामित अधिकारी, सचिव और समिति शामिल हैं। याचिकाकर्ता को यह दिखाना होगा कि इन चरणों का सही ढंग से पालन किया गया है। ध्रुव मेहता ने नामित अधिकारी के नजरिए का जिक्र किया। उन्होंने सचिव के जवाब पर कहा कि केवल धाराएं दोहराने से काम नहीं चलेगा। उच्चतम न्यायालय ने इस तरीके की आलोचना की है। संतुष्टि उपलब्ध जानकारी और सामग्री के आधार पर होनी चाहिए।

कांग्रेस केंद्र पर हमलावर- जयराम रमेश बोले- एनडीए बना 'नेशनल डिफेक्टर अलायंस', लगाए पार्टियों को तोड़ने का आरोप

नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विपक्षी दलों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश ने एनडीए को नेशनल डिफेक्टर अलायंस यानी राष्ट्रीय दल-बदलु गठबंधन का नाम दिया है। उनका कहना है कि सरकार यह सब विपक्षी दलों का मनोबल तोड़ने के लिए कर रही है। जयराम रमेश ने 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में हुई घटना का हवाला दिया। उस दिन सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया था। संविधान संशोधन विधेयक पर हुई वोटिंग में सरकार को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। सरकार के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष ने इसके खिलाफ 230 वोट डाले। रमेश के अनुसार, इस हार ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बहुत परेशान कर दिया है। उन्होंने इसे गृह मंत्री का अपमान बताया क्योंकि वे अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी जरूरी आंकड़ा नहीं जुटा पाए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अब सरकार अपनी संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे दलों को तोड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री

मानसून सत्र से पहले दो-तिहाई बहुमत चाहते हैं ताकि वे संसद का विशेष सत्र बुला सकें। रमेश ने कहा कि 16 अप्रैल को भी इसी उम्मीद में विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष की एकता की वजह से सरकार को केवल 298 वोट ही मिल सके। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला करार दिया। रमेश ने गृह मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जिस कुर्सी पर कभी सरदार पटेल बैठते थे, आज वहां बैठकर ऐसी राजनीति की जा रही है। जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार यही रणनीति राज्यसभा में भी अपना रही है। वहां सांसदों से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार चाहे जो कर ले, उसे दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलेगा। इन घटनाक्रमों के बीच आठ जून को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें 23 दलों के प्रतिनिदि शामिल हुए थे। जिससे विपक्ष का मनोबल ऊंचा है। इस समय महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बड़ी राजनीतिक हलचल चल रही है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों के टूटने की खबरें हैं। दावा किया जा रहा है कि 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी ने कहा है कि 6 सांसदों ने शिंदे गुट का साथ देने का फैसला किया है, हालांकि पार्टी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने 14 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने अपने गुट का विलय त्रिपुरा की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया में करने के लिए पत्र दिया है।

सम्पादकीय...

अस्थायी विराम?

जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच हस्ताक्षरित 14-बिंदुओं वाला समझौता हाल के वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाओं में से एक माना जा रहा है। कई महीनों तक चले सैन्य संघर्ष, क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बाद यह समझौता पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि यह अंतिम शांति संधि नहीं है, बल्कि एक प्रारंभिक ढांचा है, फिर भी इसके राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। समझौते का पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दोनों देशों तथा उनके सहयोगियों द्वारा सैन्य गतिविधियों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की घोषणा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की बात कही गई है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हालिया संघर्ष केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें इजराइल, हिज्बुल्लाह और अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थीं। हालांकि दस्तावेज़ में इजराइल और हिज्बुल्लाह का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन समझौते की सफलता काफी हद तक उनके व्यवहार पर निर्भर करेगी। दूसरा बिंदु दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। यह एक प्रतीकात्मक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। लंबे समय से अमेरिका पर ईरान में शासन परिवर्तन की नीति अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। इस समझौते से संकेत मिलता है कि वाशिंगटन अब कम से कम आधिकारिक रूप से ईरानी शासन को अस्थिर करने की नीति से पीछे हट रहा है। इससे दोनों देशों के बीच अविश्वास कम करने में मदद मिल सकती है। तीसरे बिंदु के अनुसार, दोनों पक्ष 60 दिनों के भीतर एक अंतिम और व्यापक समझौते पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यह समयसीमा महत्वाकांक्षी है क्योंकि दोनों देशों के बीच दशकों पुराना अविश्वास और अनेक जटिल मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। इनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय मिलिशिया समूहों को समर्थन और अमेरिकी प्रतिबंध जैसे विषय शामिल हैं। चौथा बिंदु वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा और ईरान के आसपास तैनात अतिरिक्त सैन्य बलों को वापस बुलाएगा। यह कदम विश्व व्यापार के लिए जीवनरेखा माने जाने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य यातायात बहाल करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विश्व के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। यदि यह जलमार्ग सुरक्षित और खुला रहता है तो अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में स्थिरता आ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। समझौते के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक ईरान को मिलने वाली आर्थिक राहत है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है, जिससे ईरान फिर से वैश्विक तेल बाजार में सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा। इसके अलावा, ईरान की जमी हुई संपत्तियों तक पहुंच और लगभग 300 अरब डॉलर तक की संभावित वित्तीय सहायता या निवेश का रास्ता भी खुल सकता है। यह ईरान की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अवसर है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इतनी बड़ी आर्थिक रियायतें ईरान को बिना पर्याप्त सुरक्षा गारंटी के देना जोखिमपूर्ण हो सकता है। समझौते का सबसे संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। आश्चर्यजनक रूप से इस मसौदे में इस विषय पर बहुत कम स्पष्टता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इसे अधूरा दस्तावेज मान रहे हैं। अमेरिका की प्राथमिक चिंता हमेशा से यह रही है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करे, जबकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आवश्यक बताता रहा है। अंतिम समझौते की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष इस मुद्दे पर किस प्रकार का समझौता करते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्पष्ट किया है कि ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने वाले समूहों को समर्थन देना बंद करना होगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान हिज्बुल्लाह, हौथी विद्रोहियों और अन्य सहयोगी संगठनों के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करे। दूसरी ओर, ईरान इसे अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। इसलिए यह मुद्दा आगामी वार्ताओं में सबसे कठिन विषयों में से एक होगा। समझौते का चौदहवाँ और अंतिम बिंदु विशेष महत्व रखता है। इसके अनुसार अंतिम शांति समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के बाध्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से मान्यता दी जाएगी। इससे समझौते को अंतरराष्ट्रीय वैधता प्राप्त होगी और भविष्य में किसी भी पक्ष के लिए इसे एकतरफा रूप से छोड़ना कठिन हो जाएगा। चूंकि सुरक्षा परिषद में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे स्थायी सदस्य शामिल हैं, इसलिए यह समझौता केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व का बन जाता है। कुल मिलाकर, अमेरिका-ईरान 14-बिंदु शांति योजना पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह युद्धविराम, आर्थिक सहयोग और कूटनीतिक संवाद का नया ढांचा प्रस्तुत करती है। हालांकि इसके सामने अनेक चुनौतियां हैं—विशेष रूप से परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सहयोगी समूहों की भूमिका और राजनीतिक अविश्वास। यदि दोनों पक्ष अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करते हैं, तो यह समझौता न केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों को नया स्वरूप दे सकता है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में शांति और आर्थिक स्थिरता का आधार भी बन सकता है। लेकिन यदि वार्ताएँ विफल होती हैं, तो यह समझौता केवल एक अस्थायी विराम साबित हो सकता है। इसलिए आने वाले 60 दिन इस पहल की वास्तविक सफलता का निर्धारण करेंगे।

जी 7 शिखर सम्मेलन 2026- ईरान समझौते ने कैसे बदली ट्रंप की कूटनीतिक रणनीति

फ्रांस के अल्पाइन शहर एवियन-ले-बैंस में आयोजित जी 7 शिखर सम्मेलन 2026 कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध ने वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। लेकिन सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अक्सर बहुपक्षीय मंचों और अंतरराष्ट्रीय बैठकों के आलोचक रहे हैं, इस बार अपने सहयोगी देशों के बीच अपेक्षाकृत सहज और सकारात्मक दिखाई दिए। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच हुआ प्रारंभिक शांति समझौता था, जिसे जी 7 देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। कुछ सप्ताह पहले तक ट्रंप अपने यूरोपीय सहयोगियों से नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इज़रायली सैन्य अभियान में भाग लेने से इनकार कर दिया था। ट्रंप का मानना था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कठोर सैन्य कार्रवाई आवश्यक थी। लेकिन युद्ध के बाद जब अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते का मसौदा सामने आया, तो वही सहयोगी देश इस पहल के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। जी 7 नेताओं ने न केवल इस समझौते का स्वागत किया बल्कि संयुक्त बयान में ट्रंप के «मजबूत नेतृत्व» की भी प्रशंसा की। यह घटनाक्रम ट्रंप की विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि जी 7 में उन्हें अभूतपूर्व एकता देखने को मिली। उनका मानना था कि सभी देशों की प्राथमिकता अब क्षेत्रीय स्थिरता और तेल कीमतों को नियंत्रित करना है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ था और कई देशों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए ईरान समझौते को केवल राजनीतिक सफलता नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम माना गया। हालांकि इस समझौते की सफलता को लेकर अभी भी कई प्रश्न बने हुए हैं। दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप ने स्वयं इस समझौते की जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पर डाल दिया। वेंस इस समझौते के प्रमुख वार्ताकारों में शामिल रहे हैं और वे लगातार मीडिया में इसकी वकालत करते रहे हैं। जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि यदि समझौता सफल होता है तो क्या वे इसका श्रेय लेंगे और असफल होने पर वेंस को दोष देंगे, तो ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें यह विचार पसंद है। यह बयान ट्रंप की राजनीतिक शैली को दर्शाता है, जिसमें सफलता का श्रेय लेने और असफलता की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की प्रवृत्ति अक्सर देखी जाती है। जी 7 सम्मेलन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यूक्रेन युद्ध को लेकर सामने आया। पिछले कुछ वर्षों में ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के बीच यूक्रेन को लेकर मतभेद रहे हैं। ट्रंप बार-बार यह कहते रहे हैं कि यूक्रेन के पास रूस के खिलाफ लड़ाई में «कोई मजबूत पत्ता» नहीं है और उसे समझौते की दिशा में बढ़ना चाहिए। लेकिन इस बार उन्होंने संयुक्त बयान में यूक्रेन के लिए «अटूट समर्थन» व्यक्त किया। जी 7 देशों ने यूक्रेन को अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणाली, इंटरसेप्टर मिसाइलें और लंबी दूरी की सैन्य क्षमताएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। यह संकेत देता है कि यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप को यूक्रेन की स्थिति और उसके रणनीतिक महत्व को लेकर कुछ हद तक प्रभावित किया है। सम्मेलन में चीन भी चर्चा का प्रमुख विषय रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने चीन पर वैश्विक आर्थिक असंतुलन पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीनी उद्योगों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी, अत्यधिक उत्पादन क्षमता और कमजोर घरेलू मांग के कारण विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही है। जी 7 देशों ने संयुक्त बयान में आर्थिक दबाव और व्यापारिक असंतुलन के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की बात कही। लेकिन चीन को लेकर ट्रंप का दृष्टिकोण अपने सहयोगियों से कुछ अलग दिखाई दिया। सम्मेलन के समापन पर उन्होंने चीन और रूस दोनों का धन्यवाद किया कि उन्होंने ईरान संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया। ट्रंप ने विशेष रूप से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रशंसा करते हुए कहा कि चीन ने ईरान को हथियार उपलब्ध नहीं कराए, जिससे संघर्ष और जटिल नहीं हुआ। यह बयान जी 7 देशों की चीन-विरोधी चिंताओं और ट्रंप की व्यवहारिक कूटनीति के बीच अंतर को दर्शाता है। इस सम्मेलन का एक दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप को पूरे सम्मेलन में बनाए रखने में सफलता हासिल की। पिछले वर्ष ट्रंप जी 7 सम्मेलन समाप्त होने से पहले ही वापस लौट गए थे। लेकिन इस बार मैक्रों ने उन्हें वर्साय के ऐतिहासिक महल में रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया। फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार यह केवल औपचारिक भोज नहीं था, बल्कि फ्रांस और अमेरिका के ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीकात्मक उत्सव भी था। माना जा रहा है कि इस व्यक्तिगत कूटनीतिक पहल ने ट्रंप को सम्मेलन में सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुल मिलाकर जी 7 शिखर सम्मेलन 2026 ने यह दिखाया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संवाद और व्यक्तिगत कूटनीति आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान समझौते ने ट्रंप को अपने सहयोगियों के साथ संबंध सुधारने का अवसर दिया, जबकि यूक्रेन और चीन जैसे मुद्दों पर भी कुछ हद तक साझा समझ विकसित होती दिखाई दी। हालांकि कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं और ईरान समझौते का भविष्य अनिश्चित है, फिर भी यह सम्मेलन इस बात का संकेत देता है कि वैश्विक संकटों के समाधान के लिए बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि जी 7 में दिखाई गई यह एकता केवल कूटनीतिक बयानबाजी थी या वास्तव में विश्व राजनीति में एक नए सहयोगात्मक दौर की शुरुआत।

मानवता की परीक्षा

विश्व शरणार्थी दिवस केवल एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अंतःकरण को झकझोरने वाला अवसर है। यह दिवस उन करोड़ों लोगों के दर्द, संघर्ष और टूटे हुए सपनों की याद दिलाता है, जिन्हें युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु संकट और भूख ने अपने ही घरों से बेघर कर दिया। शरणार्थी केवल सीमाएँ पार करने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह अपने पीछे एक पूरा संसार छोड़कर चलने को विवश इंसान होता है। जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ता है, तो वह केवल मिट्टी नहीं छोड़ता; वह अपनी स्मृतियाँ, रिश्ते, बचपन, संस्कृति और पहचान भी पीछे छोड़ देता है। शरणार्थी बनने का दर्द केवल भूख या बेघर होने का दर्द नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से कट जाने की असहनीय पीड़ा भी है। दुनिया के अनेक देशों में आज भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी सुरक्षित बचपन नहीं देखा, जिनकी आँखों में खिलौनों की जगह बारूद और भय के दृश्य बस गए हैं। आज विश्व के कई हिस्से युद्ध और संघर्ष की आग में जल रहे हैं। कहीं बमबारी से शहर खंडहर बन रहे हैं, कहीं जातीय हिंसा इंसानियत को शर्मसार कर रही है, तो कहीं जलवायु परिवर्तन लोगों को अपने गांवों और खेतों से पलायन के लिए मजबूर कर रहा है। यह स्थिति बताती है कि आधुनिक विकास और तकनीकी प्रगति के बावजूद मानवता अभी भी शांति और संवेदना की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल होती दिखाई दे रही है।

शरणार्थियों की सबसे बड़ी त्रासदी यह होती है कि वे कहीं भी पूरी तरह अपने नहीं रह जाते। अपना देश उन्हें खो देता है और नया देश उन्हें संदेह की दृष्टि से देखता है। अस्थायी शिविरों में जीवन बिताते हुए वे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते हैं। अनेक महिलाएँ और बच्चे शोषण, तस्करी और हिंसा का शिकार बनते हैं। यह केवल राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का भी गंभीर प्रश्न है। विश्व शरणार्थी दिवस हमें यह सोचने के लिए विवश करता है कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न क्यों होती हैं जहाँ इंसान को अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते; वे मनुष्यता के भीतर भी गहरे घाव छोड़ जाते हैं। सत्ता और स्वार्थ की लड़ाइयों का सबसे बड़ा मूल्य हमेशा आम नागरिक चुकाते हैं। जिन बच्चों ने कभी राजनीति नहीं समझी, उन्हें भी विस्थापन और भय की सजा मिलती है।आज जलवायु परिवर्तन भी शरणार्थियों की संख्या बढ़ाने वाला बड़ा कारण बनता जा रहा है। सूखा, बाढ़, समुद्री जलस्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाएँ लाखों लोगों को अपने घरों से बेदखल कर रही हैं। आने वाले वर्षों में जलवायु शरणार्थी विश्व के सामने सबसे बड़ी मानवीय चुनौती बन सकते हैं। यह चेतावनी है कि यदि प्रकृति का संतुलन नहीं बनाया गया, तो विस्थापन केवल युद्ध क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की संस्कृति सदैव «वसुधैव कुटुम्बकम्» की रही है। हमारे देश ने विभिन्न समयों में अनेक शरणार्थियों को आश्रय देकर मानवता का परिचय दिया है। किंतु केवल सहानुभूति पर्याप्त नहीं है; वैश्विक स्तर पर स्थायी शांति, न्यायपूर्ण नीतियाँ और मानवीय दृष्टिकोण विकसित करना भी आवश्यक है। यह भी सच है कि शरणार्थी बोझ नहीं होते। अवसर मिलने पर वही लोग समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें केवल दया नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और पुनर्वास की आवश्यकता होती है।

आधुनिक जीवन की चुनौतियों का प्रभावी समाधान है योग

आज का युग अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति, तीव्र प्रतिस्पर्धा और व्यस्त जीवनशैली का युग है। आधुनिक सुविधाओं ने जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही मानसिक तनाव, चिंता, अनियमित दिनचर्या और अनेक जीवनशैली संबंधी रोगों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे समय में योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने की एक प्रभावी पद्धति के रूप में सामने आता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया योग के महत्व को स्वीकार कर रही है और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रही है। मानव शरीर और मन के बीच गहरा संबंध होता है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तब अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, अवसाद, चिंता और कई अन्य तनावजनित बीमारियां आधुनिक जीवन की सामान्य चुनौतियां बन चुकी हैं। इन समस्याओं के समाधान की तलाश में दुनिया ने फिर से योग जैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान की ओर रुख किया है। अनेक चिकित्सकीय और वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि योग शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग को केवल कुछ आसनों या व्यायामों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। यह जीवन को समझने और सही ढंग से जीने का विज्ञान है। योग व्यक्ति को अपने शरीर, मन और आत्मा के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। यह सप्ताह में एक बार की जाने वाली गतिविधि नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सतत प्रक्रिया है। नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग की विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और जीवनशैली के अनुसार मार्ग चुन सकता है। भारतीय परंपरा में हठ योग, राज योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग जैसे अनेक मार्ग बताए गए हैं। कोई व्यक्ति प्राणायाम, ध्यान, आसन, विश्राम अथवा इन सभी का समन्वित अभ्यास कर सकता है। योग की यही लचीलापन उसे सार्वभौमिक बनाती है और हर आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध करती है। योग का अभ्यास मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है तथा व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित बनाता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर में लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त यह श्वसन तंत्र को बेहतर बनाता है तथा शरीर में जीवन शक्ति का संचार करता है। देखने में योग केवल शरीर को खींचने और मोड़ने की प्रक्रिया प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में इसका प्रभाव व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद से योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग नियमित रूप से योग का अभ्यास कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि योग आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सरल और प्रभावी समाधान प्रदान करता है। वर्तमान समय में पर्यावरणीय परिवर्तन भी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। मौसम के असामान्य बदलाव, प्रदूषण, हरित क्षेत्रों में कमी और बदलती जीवनशैली शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर असर डाल रही है। ऐसे में योग शरीर को मजबूत बनाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। यह व्यक्ति को प्रकृति के साथ जोड़ता है और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण विकसित करता है। आज अधिकांश लोगों के पास समय कम और जिम्मेदारियां अधिक हैं। कार्यस्थल का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और व्यक्तिगत चुनौतियां मानसिक तनाव को बढ़ा रही हैं। इसका सीधा प्रभाव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और न्यूरोलॉजिकल विकारों के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे समय में योग एक प्रभावी सहयोगी के रूप में उभरकर सामने आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि योग तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और संतुलित रखने में सहायता करता है। ध्यान, प्राणायाम और मंत्रों का नियमित अभ्यास मस्तिष्क को शांत करता है तथा एकाग्रता बढ़ाता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान और श्वास संबंधी अभ्यास करता है, तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक तनाव में कमी आती है। यही कारण है कि अनेक चिकित्सक भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में योग को सहायक उपचार के रूप में अपनाने की सलाह देते हैं। माइग्रेन, अनिद्रा, चिंता और तनाव जैसी समस्याओं में योग विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। योग व्यक्ति को स्वयं के भीतर झांकने और मानसिक शांति प्राप्त करने का अवसर देता है। नियमित अभ्यास से मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है तथा व्यक्ति अधिक सजग और संतुलित महसूस करता है। आधुनिक अनुसंधान भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि योग मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत को योग की जन्मभूमि माना जाता है। यहां प्राचीन काल से विभिन्न प्रकार की योग परंपराएं विकसित हुई हैं, जिनका उद्देश्य मानव जीवन को अधिक स्वस्थ, संतुलित और सार्थक बनाना रहा है। आज विश्व के विकसित देशों ने भी योग को अपनाया है क्योंकि वे इसके व्यावहारिक लाभों को समझ चुके हैं। योग केवल बीमारी के उपचार का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली को बनाए रखने का एक प्रभावी साधन है। योग में बताए गए विभिन्न आसन शरीर की मांसपेशियों, नसों और तंत्रिकाओं को सक्रिय करते हैं। इससे शरीर की कार्यक्षमता में सुधार होता है और अंगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है। साथ ही प्राणायाम और ध्यान मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि योग को समग्र स्वास्थ्य का विज्ञान कहा जाता है। वर्तमान समय में जब जीवन की गति लगातार बढ़ रही है, तब योग व्यक्ति को रुककर स्वयं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह केवल शारीरिक फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन का आधार भी है। योग हमें स्वस्थ रहने, सकारात्मक सोच विकसित करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना समय की आवश्यकता है।

बहुत अंतर है नेहरू-मोदी और उनके युग में

हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला की कुछ पंक्तियां पंडित जवाहर लाल नेहरू और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल की तुलना पर एकदम सटीक बैठती है- 'अपने अपने युग में सबको अनुपम था अपना प्याला, अपने अपने अपने युग में सबकी अनुपम थी अपनी हाला। लेकिन वृद्धों से जब पूछा, एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले अब न रही वो मधुशाला।' हालांकि तुलना की यह तैयारी 2014 से ही चल रही थी और आखिरकार 2026 में तथ्य और तर्क को दरकिनार करके उसे करने में सरकार और पार्टी और उनकी तमाम मशीनरी जुट गई है। जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे तो एक पत्रिका ने अर्धनारीश्वर की तरह ही मोदी नेहरूकार का प्रतिच्छवि कवर पर बनाया था और उसका जोर यह था कि भाजपा मोदी के रूप में नेहरू जैसा आइकन तैयार कर रही है। उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां भले अलग हों लेकिन आर्थिक नीतियों का खाका वही है। आज मोदी जी के प्रशंसक नेहरू के प्रधानमंत्री रहने का रिकार्ड तोड़ने का दावा करते हुए उन्हें बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। जो कि हर लिहाज से अनुचित है। ऐसी तुलना न सिर्फ कांग्रेस के पैमाने से अनुचित है, भाजपा और संघ के पैमाने से भी अनुचित है। इस तुलना से भाजपा और संघ का पिछले दो तीन दशक से चलाया जा रहा पूरा आख्यान भरभरा जाता है। जिन नेहरू की विफलताओं को गिनाने के लिए कई वेबसाइट बनाई गईं और संसद से लेकर तमाम पत्र पत्रिकाओं में झूठा इतिहास परोसा गया, ऐसे नेहरू से तुलना करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर नेहरू इतने बुरे हैं जितना कि भाजपा और संघ परिवार ने लगातार प्रचारित किया है तो उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए न कि उनसे तुलना की जानी चाहिए। क्या संघ परिवार का कोई सदस्य यह कहने या सुनने का साहस करेगा कि मोदी जी इक्कीसवीं सदी के नेहरू हैं। कोई अखबार या पत्र या चैनल इस बात को ठकुरसोहाती में भी कहने का साहस नहीं कर सकता। क्योंकि यह बात उनके पक्ष को बुरी लगेगी। दूसरी बात यह है कि नेहरू को महज 12 साल तक प्रधानमंत्री बताने वाला तथ्यहीन और अनैतिहासिक दावा नेहरू पर लगाए जाने वाले संघ परिवार के तमाम आरोपों को ही सिरे से खारिज कर देता है—जैसे कि नेहरू पटेल को दरकिनार करके महात्मा गांधी को खुश करके प्रधानमंत्री बन गए थे। और अगर नेहरू प्रधानमंत्री ही नहीं थे, तो सरदार पटेल आजाद भारत के पहले गृहमंत्री और उपप्रधानमंत्री कैसे कहे जा सकते हैं। फिर तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी न तो भारत के औद्योगिक मंत्री थे और न ही पटेल ने भारत का एकीकरण किया और न ही नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद और डॉ अंबेडकर ने मिलकर भारत का संविधान बनाया। फिर तो नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भाग्य वधू के साथ की गई प्रतिज्ञा वाला ऐतिहासिक भाषण भी नहीं दिया था। मोदी जी को खुश करने के चक्कर में भारतीय इतिहास को सिर के बल खड़ा करने का यह प्रयास किसी भी सरकार और व्यवस्था को इतिहास में सीधा खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ेगा। वह सरकार अपने कर्मों और विचार में अष्टावक्र की तरह से ही मौजूद रहेगी। दोनों नेताओं के स्वभाव और युग में जमीन आसमान का अंतर है और उसे खुले दिलो दिमाग से देखने पर ही दोनों के साथ न्याय किया जा सकेगा। जाहिर सी बात है कि नेहरू एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे और मोदी सामान्य परिवार में। पर इसमें उन दोनों का कोई दोष नहीं है और न ही इस आधार पर किसी की आलोचना करने का या किसी को छोटा बताने का कोई औचित्य बनता है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। जन्म से उसे थोड़ी बहुत मदद मिलती है लेकिन अच्छे और ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले सारे लोग बड़े काम नहीं कर पाते, बड़े पद पर भले ही पहुंच जाएं। यही बात सामान्य परिवार में पैदा होने वाले लोगों के लिए भी सही है। निश्चित तौर पर सामान्य परिवार में पैदा होने वाले का संघर्ष बड़ा होता है लेकिन इतिहास में ऐसे लोग भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं और अपना राज्य तक कायम किया है। लेकिन इतिहास उन्हें उनकी न्यायप्रियता और लोककल्याणकारी कामों के लिए ही याद करता है न कि तुगलकी फैसलों के लिए। लोकतांत्रिक आदर्शों के मुताबिक महानता इस बात में है कि देश और समाज के लिए आप का योगदान क्या रहा और आप ने अपने को कितना परिष्कृत या डिक्लास किया। शास्वत नैतिक मूल्यों की कसौटी पर आप कितने खरे उतरे हैं। जाहिर सी बात है कि मोदी जी को डिक्लास करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें तो अपने अभावग्रस्त बचपन को विस्मृत करने के लिए दस लाख का सूट पहनने और तमाम विलासिता का प्रदर्शन करने का शौक रहा और वह उन्होंने जमकर किया और अब भी कर रहे हैं। लेकिन नेहरू ने गांधी के प्रभाव में अपने को डिक्लास किया। सख्त बिस्तरों पर सोना, जमीन पर सोना, साधारण भोजन करना जेल में रहना, यह सब उन्होंने साधा। उनके इन प्रयासों से उनके पिता और देश के बड़े वकील मोतीलाल नेहरू थोड़े परेशान भी रहते थे। नेहरू की हैरो कैम्ब्रिज की पढ़ाई लिखाई और उनकी बौद्धिक अभिरुचि मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी में कहीं से नहीं दिखती। उनकी अपेक्षा करना उचित भी नहीं है। न तो उन्हें डिस्कवरी आफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक और पिता के पत्र पुत्री के नाम जैसे ग्रंथ लिखने की जरूरत है और न ही अभिरुचि और न ही बौद्धिक बेचैनी। मोदी जी ने 'एग्जाम वारियर' जैसी किताब लिखी है और उनके 'मन की बात' को भी प्रकाशित किया गया है जिनकी तुलना नेहरू के ग्रंथों से कतई नहीं हो सकती। लेकिन देश की आजादी के लिए तकरीबन एक दशक तक जेल में बिताने वाले नेहरू का रिकार्ड मोदी जी कैसे तोड़ेंगे? अगर विनायक दामोदर सावरकर को छोड़ दिया जाए तो हिंदुत्व विचार के किसी नेता के खाते में इतनी लंबी जेल यात्रा नहीं है। नेहरू और कांग्रेस पार्टी पर एकहद तक भारत के विभाजन का दोष भी जाता है लेकिन उन्हें इस बात का श्रेय भी जाता है कि उन्होंने एक टूटे हुए देश के बाकी बचे हिस्से को जोड़ने संवारने और बनाने का काम किया। लाखों शरणार्थियों को बसाया और विभाजन के रक्तरंजित समुद्र से निकालकर भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया।'

हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के', शायद यह गीत उन्हीं पर लिखा गया था। नेहरू को चीन से विश्वासघात मिला और मिला देश को पराजय का गहरा जख्म, जिससे संवेदनशील और कवि हृदय नेहरू उबर नहीं पाए और आखिरकार चीन के आक्रमण के एक साल बाद यानी 1964 में दुनिया से विदा हो गए। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से उन्होंने औपनिवेशिक वर्चस्व के विरोध में दुनिया में एक नई चेतना एक नए आह्वान का संचार किया और उसे नेतृत्व दिया। इस नाते नेहरू का अमेरिका से लेकर सोवियत संघ तक गहरा सम्मान था। तीसरी दुनिया तो उन्हें अपना रहनुमा मानती ही थी। नेहरू ने भारत और दुनिया के कई देशों को औपनिवेशिक वर्चस्व से निकाला था और कोरिया और वियतनाम जैसे कई विवादों का हल भी निकाला। वे विऔपनिवेशीकरण के वैश्विक अभियान के अगुआ थे, इसीलिए भारत के आजाद होने के बाद दुनिया के क्रम से सौ देश औपनिवेशिक गुलामी से आजाद हुए थे। जबकि मोदी जी ने भारत की संप्रभुता को अमेरिका जैसे नवउपनिवेशवादी देश के सामने झुका दिया। अगर नरसिंहराव और मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीतियों के माध्यम से आर्थिक औपनिवेशीकरण की ओर देश को झुकाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस चक्र को राजनीतिक अंजाम तक पहुंचाया। एक तरह से देखें तो भारत महाशक्तियों के औपनिवेशीकरण अभियान का सहयोगी बन गया है।

नेहरू ने 1930 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ही नहीं पेश किया, उन्होंने संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर संविधान का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया और आखिर में उद्देशिका भी पेश की। नेहरू के नेतृत्व में ही भारत को धर्मनिरपेक्ष संविधान मिला और उसी नाते भारत अब तक एकजुट है अल्पसंख्यकों ही नहीं देश के निरक्षर लोगों को भी वयस्क मताधिकार मिला और सभी को संविधान के समक्ष बराबरी का हक हासिल हुआ साथ ही नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन देने की प्रतिज्ञा भी की गई। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्षता का ढांचा कमजोर किया गया, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया गया

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने करन ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैण्डपावला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/[illegible])

छठ घाट सुंदरीकरण कार्य का नपाध्यक्ष विनय जायसवाल ने किया निरीक्षण

पडरौना (कुशीनगर)। नगर पालिका परिषद पडरौना द्वारा नगर के विकास एवं जनसुविधाओं के विस्तार के तहत कराए जा रहे कार्यों की श्रृंखला में नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने हनुमान इंटर कॉलेज के समीप स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज छठ घाट पर चल रहे सुंदरीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता एवं तकनीकी मानकों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। नपाध्यक्ष ने कहा कि छठ पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशेषकर माताएं एवं बहनें, इस घाट पर पूजा-अर्चना के लिए पहुंचती हैं। उनकी सुविधा, सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए घाट का विकास एवं सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्य पूर्ण होने के बाद श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नगर के नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विकास कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है। इस अवसर पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संतराम सरोज, अवर अभियंता रामबहादुर प्रसाद, पवन गौंड, संतोष चौहान, राकेश जायसवाल, मंथन सिंह, आकाश वर्मा, ओम कुशवाहा, प्रवीण तिवारी, ललित चौबे, प्रिंस शर्मा सहित नगर पालिका कर्मी, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में गिनाई गई मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां

कुशीनगर।

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कसया स्थित राजघराना रिसॉर्ट में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रमापति राम त्रिपाठी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में आरपीएन सिंह उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस अवधि में गरीब कल्याण, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शौचालय, राशन और उज्ज्वला जैसी योजनाओं के माध्यम से व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2027 तक तीसरे स्थान पर पहुंचने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने रक्षा, अनुसंधान, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नारी सशक्तिकरण और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वसमाज की पार्टी है और देश की एकता एवं अखंडता के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विरासत और विकास को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति ने देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान दिलाई है तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रबुद्ध समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री रामगोपाल गुप्ता ने किया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष किरन जायसवाल सहित पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

तकनीकी दक्षता की बुनियाद पर करीब 31 लाख के 108 मोबाइल फोन बरामद

महराजगंज।

साइबर थाने में दर्ज शिकायतों को लेकर पुलिस टीम से गंभीरता दिखाई है। करीब 31 लाख के 108 मोबाइल खो गए थे। इसकी शिकायत दर्ज हुई तो सीईआईआर पोर्टल (सेंट्रल इक्यूपमेंट आइडेंटी रजिस्टर) के जरिए मोबाइल ढूंढ़ लिया गया। पुलिस की ओर से मोबाइल बरामद कर उनके स्वामी को सौंपा गया। खोया हुआ मोबाइल पाकर लोगों ने खुशी जाहिर की। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी की ओर से मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कीमती स्मार्ट फोन को CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के माध्यम से खोजा गया। करीब दो माह के भीतर 108 मोबाइल गुम होने की शिकायत साइबर सेल को मिली। पुलिस टीम की ओर से तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए कार्रवाई तेज की गई तो यह सफलता मिल गई। जनपद में

खोए हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 108 अदद मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए गए। इन सभी मोबाइल फोनों की अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 31 लाख रुपये है। यह सफलता सर्विलांस सेल की ओर से सीईआईआर पोर्टल की तकनीकी सहायता से हासिल की गई। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया की सर्विलांस टीम ने आईएमईआई नंबर आधारित ट्रैकिंग, विस्तृत सर्विलांस और आधुनिक तकनीकी टूल्स का प्रभावी उपयोग कर इन मोबाइलों का पता लगाया। सभी संबंधित मोबाइल मालिकों को बुलाकर पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत उनके मोबाइल फोन सुपुर्द किया गया। मोबाइल वापस मिलने पर मालिकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने

सीईआईआर पोर्टल (सेंट्रल इक्यूपमेंट आइडेंटी रजिस्टर) के जरिए ढूंढा गया मोबाइल, दर्ज हुई शिकायतों पर गंभीर हुई पुलिस

महराजगंज पुलिस प्रशासन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक ने इस उपलब्धि पर सर्विलांस सेल की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि ÷जनता की छोटी से छोटी समस्या का त्वरित समाधान करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तकनीक आधारित पुलिसिंग आज की आवश्यकता है और सीईआईआर पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग कर नागरिकों की संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए समर्पित है । उन्होंने नागरिकों से अपील की किसी भी मोबाइल चोरी या गुम होने की स्थिति में तत्काल सर्विलांस सेल या नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं।

आईजीआरएस निस्तारण में लापरवाही पर भड़के डीएम, बीएसए और तहसीलदार समेत पांच अफसरों को चेतावनी

देवरिया। जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर आने वाली जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और अमानक रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा विधिक रुख अख्तियार किया है। पोर्टल पर दर्ज मामलों के निस्तारण और शिकायतकर्ताओं से सीधे मिले फीडबैक में भारी विसंगतियां पाए जाने पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने पांच जिम्मेदार जिला स्तरीय अधिकारियों को कड़ी प्रशासनिक चेतावनी जारी की है। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत दी है कि सभी अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाएं, क्योंकि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही की पुनरावृत्ति होने पर सीधे विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासनिक समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विभागीय स्तर से पोर्टल पर मामलों को निस्तारित दिखाकर फाइलें तो बंद कर दी गईं, लेकिन जब कलेक्ट्रेट स्तर से फरियादियों से दूरभाष पर फीडबैक लिया गया तो धरातल पर स्थिति बिल्कुल उलट मिली। इस विधिक विसंगति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार देवरिया, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ), अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रुद्रपुर को कारण बताओ नोटिस के साथ कड़ी चेतावनी दी है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शासन की मंशानुरूप आईजीआरएस पोर्टल का उद्देश्य जनता को त्वरित और पारदर्शी न्याय दिलाना है, न कि केवल आंकड़ों की बाजीगरी करना। शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही होना अनिवार्य है। कलेक्ट्रेट की इस सख्त कार्रवाई से प्रशासनिक अमले में हड़कंप है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त प्रभारियों को निर्देशित किया है कि भविष्य में किसी भी आख्या को पोर्टल पर दर्ज करने से पूर्व मौके का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनसामान्य का भरोसा प्रशासनिक व्यवस्था पर सुदृढ़ बना रहे।

बस से गिरकर एक व्यक्ति की मौत

आनन्दनगर महराजगंज। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पुरंदरपुर ओवर ब्रिज पर बस से गिरकर विद्यामान श्रेष्ठ पुत्र चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ 42 वर्षीय निवासी ग्राम चुटपानी, जनपद चितवन, नेपाल राष्ट्र, की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग के पुरन्दरपुर फ्लाईओवर पर गुरुवार को सुबह साढ़े पांच बजे हुई हैं। उक्त घटना एक प्राइवेट बस जो गोरखपुर से सोनौली के लिए जा रही थी पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित फ्लाईओवर पर घटित हुई । पुरंदरपुर थाना प्रभारी गौरव कनौजिया ने बताया कि उक्त घटना बस से गिरकर हुई है गेट पर ही विद्यमान श्रेष्ठ खड़ा था हादसे वाली प्राइवेट बस थी जो सोनौली जा रही थी। मृतक व्यक्ति बस के गेट पर खड़ा था इस वजह से अचानक गिर गया सवारी यात्रियों ने बार-बार मना किया लेकिन नहीं माना। थानाध्यक्ष ने बताया कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है।शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया।

फंदे से लटका मिला युवक का शव

आनंद नगर महाराजगंज। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र मे ग्राम सभा धुसवाकला निवासी एक युवक के कुंडी से लटक कर मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। युवक, चन्द्र प्रकाश मिश्रा पुत्र त्रियुगी मिश्रा,38 वर्षीय निवासी धुसवाकला,पुरन्दरपुर ने अपने कमरे को अंदर से बंद करके चादर से पंखे की कुंडी में लटक कर फसरी लगा लिया परिजनों को सुबह लगभग 6:00 बजे छः इसकी जानकारी हुई इसकी तत्काल सूचना परिजनों द्वारा पुरंदरपुर थाने के पुलिस को दी गई मौके पर पुरंदरपुर की पुलिस पहुंचकर दरवाजे को तोड़कर मृतक को कुंडी से लटकते हुए नीचे उतारा। परिजनों ने बताया कि चंद्र प्रकाश मिश्र कल देर रात को घर आए और खाना खाकर कमरे में सो गए गुरुवार की सुबह कमरे में फन्दे से लटकता देख कर पुलिस को सूचना दी गई।

मोहर्रम को लेकर कड़ा प्रशासनिक पहरा, संवेदनशील इलाकों में 31 मजिस्ट्रेट तैनात

देवरिया।

जनपद में मोहर्रम पर्व को पूर्णतः शांतिपूर्ण, सकुशल और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने विधिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी एवं पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर की संयुक्त अध्यक्षता में पीस कमेटी की एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न अंचलों से आए प्रबुद्ध नागरिकों और ताजियादारों से सीधा संवाद स्थापित कर त्योहार को आपसी समन्वय और पारंपरिक मर्यादा के साथ मनाने की विधिक अपील की गई। ?प्रशासनिक मुस्तैदी को रेखांकित करते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि सुरक्षा के विन्यास को अभेद्य बनाने के लिए जनपद के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर 31 मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही तहसीलवार वरिष्ठ नोडल अधिकारी

भी नामित किए गए हैं। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने निर्देश दिए कि जुलूस के परंपरागत मार्गों पर साफ-सफाई और बिजली आपूर्ति का रोस्टर पूर्व में ही सुव्यवस्थित कर लिया जाए। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखते हुए सभी पीएचसी और सीएचसी में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित रखने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा और यातायात व्यवस्था को बाधित किए बिना केवल निर्धारित रूटों पर ही संचालन किया जाएगा। डीजे संचालकों के लिए विधिक नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने सुरक्षा व्यवस्था की विधिक समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए कि मोहर्रम जुलूस में ताजिया की ऊंचाई किसी भी दशा में निर्धारित 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं और बच्चों को अनुशासन में रखने तथा किसी भी प्रकार के

ताजिया की ऊंचाई अधिकतम 12 फीट तय, अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन और नए रूट पर जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध

भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट या विवादित मुद्दों से दूर रहने की सीख दी। एसपी ने दो टूक कहा कि पुलिस बल और खुफिया विंग असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रख रहे हैं, और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार पाण्डेय के संचालन में आयोजित इस बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी वी.के. सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) रामशंकर सहित सभी क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष और विभिन्न क्षेत्रों के संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे।

शिवसेना यूबीटी की बैठक में 6 सांसदों के नहीं पहुंचने पर एक्शन, नोटिस भेजकर मांगा जवाब

***संजय राउत का दावा- शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को मिले 10 करोड़, भेजे गए राजस्थान**

नई दिल्ली। शिवसेना (उद्धव गुट) में एक बार फिर बड़ी टूट की संभावना मंडरा रही है। गुरुवार को पार्टी सांसद अनिल देसाई द्वारा दिल्ली में बुलाई गई संसदीय दल की बैठक से 9 में से 6 लोकसभा सांसद नदारद रहे। ये 6 सांसद लोकसभा में शिवसेना की कुल ताकत का दो-तिहाई हिस्सा है। शिवसेना (उद्धव गुट) ने इस खुली बगावत को देखते हुए सभी अनुपस्थित सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनकी सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ऑपरेशन टाइगर की अटकलें

महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसी अटकलें हैं कि शिवसेना के वर्तमान 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं और पाला बदलने पर विचार कर रहे हैं। इस घटनाक्रम ने 2022 में शिंदे के नेतृत्व में हुई उस बगावत की चिंताएं फिर से पैदा कर दी हैं, जिसने पार्टी को दो धड़ों में बांट दिया था।

शिवसेना ने अपने सभी सांसदों को दिल्ली स्थित संसद कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए थ्री-लाइन व्हिप जारी किया था। पार्टी के सभी 9 लोकसभा सांसदों अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय जाधव, ओमप्रकाश राजेनिंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर और राजभाऊ वाजे को उपस्थित रहना था। लेकिन बैठक के बाद सांसद राजभाऊ वाजे ने पुष्टि की कि कुल 6 सांसद इस जमावड़े से गायब रहे। बैठक में लोकसभा के सिर्फ तीन सांसदअरविंद सावंत, राजभाऊ वाजे और अनिल देसाई शामिल हुए। इनके अलावा राज्यसभा सांसद संजय राउत भी मौजूद थे।

यह गद्दारी और साजिश है - संजय राउत

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी और अनुपस्थित सांसदों की इस रणनीति को धोखा, बेईमानी, साजिश और फर्जीवाड़ा करार दिया। राउत ने कहा कि हमारे लोकसभा नेता अरविंद सावंत और मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने आज सुबह 11 बजे सांसदों की बैठक बुलाई थी। जो सदस्य इस बैठक में शामिल नहीं हुए, हम उसे पार्टी व्हिप का उल्लंघन मानते हैं। उन्होंने पार्टी के आदेशों का पालन नहीं किया है, इसलिए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राउत ने बागी सांसदों के कदमों पर सवाल उठाते हुए कहा, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, जवाब मांगे जाएंगे और हम उनकी सदस्यता रद्द करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कल लोकसभा स्पीकर से मिलकर विलय की मांग की है। हम भी अध्यक्ष से मिले थे मैं, अरविंद सावंत और अनिल देसाई। हमारी तस्वीर भी प्रकाशित हुई थी। अगर उन छह लोगों ने अध्यक्ष से मुलाकात की है, तो वे अपना चेहरा दिखाएं।

कारण बताओ नोटिस जारी

पार्टी सांसद अनिल देसाई ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया, बैठक खत्म होते ही आज कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। कार्रवाई यही है कि नोटिस देकर पूछा गया है, आप क्यों नहीं आए? आपको मैसेज किया गया था, व्हाट्सएप किया गया था और आपको वह मिला भी था। फिर भी आपने यह नहीं बताया कि आप आ रहे हैं या नहीं, इसलिए आपकी अनुपस्थिति को इसी रूप में देखा जाएगा। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि गंदी राजनीति करने के लिए बीजेपी को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बागी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा, आप अभी भी पार्टी के सदस्य हैं। आपने हमारी पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर चुनाव जीता है। यदि आप व्हिप का उल्लंघन करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होगी। टीवी पर देखा जा सकता है कि इन लोगों के निर्वाचन क्षेत्रों में जनता सड़कों पर उतर आई है। इस बार यह गद्दारी एकनाथ शिंदे और इन गद्दारों को बहुत भारी पड़ेगी। अरविंद सावंत अयोग्यता पत्र के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं।

यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया

1000 से ज्यादा ड्रोन, क्रूज मिसाइलें भी दागीं; जेलेंस्की बोले- यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा

मॉस्को/कीव। यूक्रेन ने गुरुवार को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, रातभर में करीब 1,000 ड्रोन और चार क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इनमें करीब 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा, हम यह युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र का एक ऑयल डिपो धमाके से तबाह हो गया। यहां मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। मॉस्को की कपोतन्या ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ। विस्फोट के बाद ऑयल डिपो टैंक का ढक्कन कई मीटर ऊपर उछल गया और आसमान में काले धुएं के गुबार छा गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पास के एक शॉपिंग सेंटर में भी आग लग गई। ड्रोन का

मलबा गिरने से कुछ रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई ऊंची इमारतों को खाली कराया गया। हमले के बाद मॉस्को के हवाई अड्डों पर कुछ समय के लिए उड़ानों पर रोक लगाई गई। जेलेंस्की ने मॉस्को पर हमले को पिछले हफ्ते कीव पर रूस की कार्रवाई का जवाब बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना ने उन ठिकानों को निशाना बनाया, जो रूस के युद्ध अभियान को सहारा दे रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अब समय आ गया है कि रूस युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाए। उन्होंने यूक्रेन की विभिन्न सैन्य और खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई की तारीफ भी की। हमले के समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन कजान में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के नेताओं के साथ शिखर बैठक में मौजूद थे। उन्होंने यूक्रेन के इस हमले पर अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अमेरिका-ईरान जंग खत्म

तय तारीख से एक दिन पहले समझौता

दोनों प्रेसिडेंट ने दस्तखत किए, ट्रम्प चिल्लाकर बोले- डील साइन

***ईरान के सामने ट्रम्प का 'सरेंडर'**
***न सत्ता बदली, न परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म;**
***122 लाख करोड़ रुपए बर्बाद**

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार रात को फ्रांस के वर्साय पैलेस में इससे जुड़े एमओयू पर साइन किए। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मौजूद थे।

डील पर दस्तखत करने के बाद ट्रम्प वर्साय पैलेस से बाहर आए।

इस दौरान किसी रिपोर्टर ने उनसे पीस डील को लेकर पूछा, तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, 'डील साइन हो गई है।' ट्रम्प के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। समझौते का ऐलान भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे किया गया। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इस समझौते के तहत ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म किया जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाएगी। इस समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में जेनेवा के पास लुसर्न शहर में साइन होने थे, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही इस पर दस्तखत कर दिए गए। दुनिया में तेल की कीमत तय करने वाला ब्रेंट क्रूड पिछले तीन दिनों से 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे बना हुआ है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड करीब 2फीसदी गिरकर 78 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। जंग के दौरान इसकी कीमत 114.44 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। यानी अब यह उस स्तर से करीब 35 डॉलर सस्ता हो चुका है। अमेरिका का WTI क्रूड तेल भी गिरकर करीब 74 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जो तीन महीने का सबसे निचला स्तर है।

उन्नाव को 570 करोड़ की सौगात

***सपा-कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी : बोले- अब यूपी में भ्रष्टाचार-अराजकता की जगह नहीं**

उन्नाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दोनों दलों को भ्रष्ट बताया और आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने केवल अपने-अपने परिवारों के हित में काम किया।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 101 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए ने कहा कि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्य पहले की सरकारों के लंबे कार्यकाल में नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों को यह काम करने से किसने रोका? उनमें क्षमता नहीं थी। वे अक्षम और भ्रष्ट थे। उन्होंने केवल अपने परिवारों के बारे में सोचा, गरीबों के बारे में नहीं।

सपा-कांग्रेस के लिए सिर्फ अपने परिवार गरीब

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए गरीबों का मतलब नेहरू-गांधी परिवार है, जबकि सपा के लिए गरीबों का मतलब सैफई परिवार तक सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वे किसी के बारे में नहीं सोच सकते। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर गरीबों की आवाज दबाने और अपराधियों व माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के दौरान कथित माफिया प्रभाव इतना बढ़ गया था कि राज्य में भय का माहौल था। उन्होंने रामायण के पात्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब मैं इन राज्य-संरक्षित माफियाओं को देखता हूं, तो मुझे खर, दूषण, मारीच और सुबाहु जैसे पात्र याद आते हैं।

युवाओं-किसानों की अनदेखी करने वालों को राज्य अब नहीं करेगा स्वीकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा और कांग्रेस के नेता गरीबों के बजाय माफियाओं के लिए चिंता जताते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने युवाओं, किसानों और महिलाओं के हितों की अनदेखी की है। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश विकास और विरासत दोनों के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और अब राज्य भ्रष्टाचार और अराजकता को स्वीकार नहीं करेगा।

2 दिन में 4 नीट स्टूडेंट ने किया सुसाइड

***गुजरात का छात्र छठी मंजिल से कूदा**
***तमिलनाडु की छात्रा ने लिखा- दोबारा एग्जाम से डर**

कोयंबटूर। तमिलनाडु के कोयंबटूर में नीट की तैयारी कर रही 19 साल की छात्रा अनुकीर्तना ने बुधवार सुबह जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

मौत से पहले छात्रा ने अपने चाचा और करीबी रिश्तेदारों को वॉट्सएप मैसेज भेजे थे। मैसेज में उसने लिखा- 'मैंने नीट परीक्षा दी थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का इंतजार कर रही थी, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो गई। अब दोबारा परीक्षा देने से डर लग रहा है। मेरे पापा ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया है, मैं अब उनका सामना कैसे करूंगी, नहीं जानती।' वहीं, अहमदाबाद के न्यू राणीप इलाके में बुधवार रात करीब 2:30 बजे 17 साल के छात्र ने आनंदम फ्लैट्स के ब्लॉक बी की छठी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस जांच में पता चला कि छात्र नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आत्महत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पिछले दो दिनों में नीट स्टूडेंट की आत्महत्या का यह चौथा मामला है। इससे पहले 16 जून को देहरादून में 23 साल की रिया थापा और लखनऊ में 17 साल की एक छात्रा ने सुसाइड किया था। 12 मई को नीट परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में अब तक लगभग 12 स्टूडेंट्स जान दे चुके हैं।

विरासत भी-विकास भी के 12 साल- पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विरासत भी, विकास भी अभियान के 12 साल पूरे होने पर कहा कि इस नीति के तहत भारत की सांस्कृतिक विरासत को नए जोश के साथ संरक्षित और आगे बढ़ाया जा रहा है।

एक्सपर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन वस्तुओं की वापसी और आध्यात्मिक व तीर्थयात्रा से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कदमों से लोग देश की सदियों पुरानी परंपराओं से फिर से जुड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को नए जोश के साथ संजोया, मनाया और आगे बढ़ाया जा रहा है। विरासत भी, विकास भी के विजन से प्रेरित होकर, प्राचीन वस्तुओं की वापसी से लेकर आध्यात्मिक और तीर्थयात्रा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तक के प्रयास लोगों को भारत की सदियों पुरानी परंपराओं से फिर से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी गुरुवार को विरासत भी, विकास भी अभियान के 12 साल पूरे होने पर इसकी सराहना की। X पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ-साथ विरासत के विजन ने भारत की आस्था, संस्कृति और इतिहास को एक नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। विकास भी, विरासत भी के विजन ने हमारी आस्था, संस्कृति और इतिहास को एक नई पहचान दी है। प्राचीन धरोहर स्थलों के संरक्षण, तीर्थ स्थलों के कायाकल्प और वैश्विक मंच पर भारतीय सभ्यता की गौरव-गाथा को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। शर्मा ने इस अभियान के तहत कई पहलों का जिक्र किया, जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, केदारनाथ धाम का पुनर्विकास और हड़प्पा विश्व धरोहर स्थलों को वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया है। सीएम शर्मा ने कहा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण से लेकर केदारनाथ धाम के पुनर्विकास, महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान तक, भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिला है। यह दौर भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राष्ट्रीय आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त बनाने वाला रहा है।

राहुल गांधी का छात्रों से आह्वान- छात्रों की गूंज से जुड़कर शिक्षा-रोज़गार पर उठाएं आवाज़

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को छात्रों और नौकरी चाहने वालों से हाल ही में शुरू किए गए छात्रों की गूंज अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद शिक्षा, परीक्षाओं और रोजगार से जुड़े उनके मुद्दों को सीधे सरकार तक पहुंचाना है। एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने हिंदी में लिखा कि अगर आपने पेपर लीक, परीक्षा में धोखाधड़ी या बहुत ज्यादा फ़ीस का दर्द सहा है। अगर इस सिस्टम ने आपके सपने तोड़ दिए हैं। अगर आपके परिवार ने आपकी पढ़ाई में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी है। तो सुनिए 'स्टूडेंट्स इको'

आपकी आवाज़ है। उन्होंने इस मुहिम को सिर्फ़ एक मुहिम से कहीं ज़्यादा बताया और इसे सरकार के सामने सस्ती शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षाओं और सम्मानजनक रोज़गार से जुड़ी मांगें उठाने का एक मंच कहा। गांधी ने सुझाव देकर और इससे जुड़ी याचिका पर हस्ताक्षर करके इसमें शामिल होने की अपील की और ज़ोर देते हुए कहा कि आपका एक हस्ताक्षर इस लड़ाई को मज़बूत करेगा। जितने ज़्यादा नाम होंगे, आवाज़ उतनी ही बुलंद होगी। गांधी द्वारा शेयर की गई कैंपेन की जानकारी के अनुसार, प्रतिभागी अपनी जानकारी देकर, सुझाव शेयर करके और पिटीशन पर साइन करके इसमें शामिल हो सकते हैं। यह अभियान कांग्रेस पार्टी की उस व्यापक कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत छात्रों और नौकरी चाहने वालों से जुड़े मुद्दों—जैसे परीक्षा से जुड़े विवाद, भर्ती में अनियमितताएं और पढ़ाई का खर्च—को उजागर किया जा रहा है।

मुंडन संस्कार से लौटते समय पूरा परिवार खत्म, चंबा में खाई में गिरी कार, 7 की मौत

चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बुधवार रात एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से तीन भाइयों समेत सात लोगों की मौत हो गयी। यह दुर्घटना चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में मसरूंड-हमल मार्ग पर छलुंड के पास तड़के करीब 2 बजे हुई, जब कुठेड पंचायत के अंतर्गत महल गांव के निवासियों को ले जा रहा वाहन कथित तौर पर चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क से नीचे उतर गया। पुलिस के अनुसार, वाहन के करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिरने के कारण उसमें सवार सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी। ग्रामीणों की मदद से बचाव दलों ने अंधेरे और खड़ी ढलान के कारण कठिन परिस्थितियों में अभियान शुरू किया। बाद में सभी शवों को खाई से बाहर निकाला गया।

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी- जांच में मिले सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सबूत

अयोध्या। राम मंदिर दानराशि में गड़बड़ी की जांच लगातार जारी है। एसआईटी ने लगातार चौथे दिन भी संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। बृहस्पतिवार को राम मंदिर के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से पूछताछ की गई। एसआईटी ने पिछले तीन दिनों में 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। दान गणना प्रक्रिया, मंदिर से बैंक तक धनराशि को ले जाने की प्रक्रिया समझी गई। सीसीटीवी कैमरों की जांच हुई। जांच में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के भी सबूत मिले हैं। इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। वे राम मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे। जानकारी के अनुसार एसआईटी शुक्रवार को जांच की प्राथमिक रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंप सकती है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक की जांच में जो दोषी पाए गए हैं उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। एसआईटी चंपत राय, गोपाल राव समेत राममंदिर ट्रस्ट के कई अन्य पदाधिकारियों व उनसे जुड़े लोगों से गहनता से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये लोग कई सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वहीं, दान के दिए गए रिकॉर्ड से भी एसआईटी संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसमें भी कई चीजें अस्पष्ट हैं। इसलिए एसआईटी को जांच में अधिक समय लग रहा है। विशेष जांच दल ने पूछताछ के लिए करीब दो सौ लोगों की सूची तैयार की है।

इनमें से सवा सौ लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें से कुछ से कई बार पूछताछ की है। पकड़े गए पांच संदिग्धों से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। उनके पास से रकम भी बरामद हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इन संदिग्धों ने कई नामों का खुलासा किया है, जिनको इस खेल में शामिल बताया है। एसआईटी ने उनके बयानों की तस्दीक कर रही है। अब सवाल है कि क्या एसआईटी की जांच के बीच एफआईआर दर्ज की जाएगी या जांच पूरी होने के बाद। या केस दर्ज ही नहीं होगा...ये सवाल अभी भी बना हुआ है।

दिल्ली में रेखा सरकार की अनोखी पहल, नीट परीक्षा में अभिभावकों के लिए बनाए जाएंगे कूलिंग जोन

नई दिल्ली। देशभर में 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अभूतपूर्व और मानवीय पहल करते हुए न केवल नीट परीक्षार्थियों बल्कि उनके साथ आने वाले अभिभावकों की सुविधा का भी विशेष प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहली बार है जब परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वालों के साथ-साथ उनके माता-पिता और परिजनों के आराम एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए कूलिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जहां उनके बैठने की सुविधा, स्वच्छ पेयजल, शिकंजी आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में नीट परीक्षा के लिए कुल 97 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 69 सरकारी विद्यालय में तथा 28 केंद्रीय विद्यालयों में हैं। इन परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन द्वारा विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अभिभावकों और परिजनों के बैठने, विश्राम करने तथा गर्मी से राहत पाने की समुचित व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष लाखों परिवार अपने बच्चों के भविष्य के सपनों के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी तो केंद्र के भीतर होते हैं, लेकिन बाहर कई घंटे तक प्रतीक्षा कर रहे माता-पिता की चिंता, धूप, गर्मी और असुविधा पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। दिल्ली सरकार ने इस मानवीय पहलू को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि परीक्षा के दिन अभिभावकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अब तक अक्सर देखा जाता था कि परीक्षा के दौरान परिजन कभी किसी पेड़ की छांव तलाशते थे, कभी पार्क में बैठकर समय बिताते थे, तो कभी आसपास की बाजारों में इधर-उधर भटकते रहते थे। कई लोगों को भीषण गर्मी में लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता था। अब ऐसी स्थिति नहीं होगी।

परीक्षा केंद्रों के बाहर ही उनके लिए आरामदायक प्रतीक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिविजनल कमिश्नर (डीएम) के निर्देश से संबंधित अधिकारी सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास कूलिंग जोन की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इन कूलिंग जोन में बैठने की सुविधा, स्वच्छ पेयजल, शिकंजी, ओआरएस, चाय तथा प्राथमिक चिकित्सा जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी ताकि अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल परीक्षा का सफल आयोजन नहीं, बल्कि परीक्षा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव को बेहतर बनाना है। जब अभिभावक सहज और निश्चिंत रहेंगे तो विद्यार्थियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा और युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों और उनके परिवारों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। यह पहल केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि उन लाखों माता-पिता के प्रति सम्मान का प्रतीक है जो अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि दिल्ली सरकार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी और भविष्य में देशभर में परीक्षाओं के दौरान अभिभावकों की सुविधा को भी समान महत्व दिया जाएगा।